www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 345 | जौनपुर, बुधवार, 05 अगस्त 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

दिल्ली विधानसभा सत्र 7 अगस्त से शुरू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा का छठा सत्र शुक्रवार से शुरू होगा और इसमें 7, 10 और 11 अगस्त को तीन बैठकें होंगी। स्पीकर गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू के आदेश के बाद, सत्र बुलाने का नोटिफिकेशन 31 जुलाई को जारी किया गया था। स्पीकर गुप्ता ने कहा कि सदन के सामने मौजूद कामकाज के आधार पर विधानसभा सत्र की बैठक को बढ़ाया भी जा सकता है। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने सत्र को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत जरूरी सभी नोटिस नेवा पोर्टल के जरिए डिजिटल रूप से जमा किए जाएंगे, और सदस्यों को नोटिस ब्रांच और नेवा सेवा केंद्र से मदद मिलेगी। स्पीकर गुप्ता ने कहा कि जो सदस्य नियम 280 के तहत मामले उठाना चाहते हैं, वे संबंधित बैठक से पहले वाले कामकाजी दिन शाम 5 बजे तक अपने नोटिस जमा कर सकते हैं। उन्होंने सभी सदस्यों से तय प्रक्रियाओं का पालन करने और तीन दिन के विधानसभा सत्र के दौरान कामकाज को सार्थक बनाने में सहयोग करने की अपील की। गुप्ता ने भरोसा जताया कि यह सत्र सदस्यों को जनहित के मामले उठाने और दिल्ली के लोगों से जुड़े मुद्दों पर रचनात्मक चर्चा में भाग लेने का सार्थक मौका देगा।

नीट–यूजी मामले में केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। नीट–यूजी पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। सरकार ने कोर्ट को बताया कि 2026 में लागू नए कानून के तहत अब पेपर लीक और नकल जैसे अपराधों पर कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। समाचार पत्र प्रकाशन हलफनामे में केंद्र ने कहा कि नए कानून के तहत परीक्षा में पेपर लीक, नकल या किसी भी तरह की धांधली करने वालों को 10 साल तक की जेल और 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार का मकसद भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाना है। सिस्टम में सुधार के लिए सरकार ने इंफोसिस के सह–संस्थापक नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक उच्च–स्तरीय टास्क फोर्स भी गठित की है। यह समिति मौजूदा परीक्षा प्रणाली की खामियों की समीक्षा करेगी और उसे और सुरक्षित बनाने के लिए सुझाव देगी। केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि यह टास्क फोर्स तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे के बड़े बदलाव किए जाएंगे। सरकार ने 21 जून को दोबारा हुई नीट–यूजी परीक्षा में सुरक्षा के इंतजामों का भी ब्योरा दिया।

पीएम मोदी ने कहा- श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए नया अध्याय

नई दिल्ली, (एजेंसी)। जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कहा कि इन वर्षों में जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। इसके साथ ही, पीएम मोदी ने जम्मू–कश्मीर और लद्दाख की प्रगति के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "सात साल पहले इसी दिन (5 अगस्त को) अनुच्छेद 370 और 35(।) इतिहास बन गए, जिससे जम्मू–कश्मीर और लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ। तब से जम्मू–कश्मीर और

लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं।" उन्होंने आगे लिखा, "बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता व खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। चाहे महिलाएं हों या हाशिए पर रहने वाले समुदाय, जिन्हें दशकों तक उनके बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, उन्हें भारत के संविधान के पूर्ण कार्यान्वयन के कारण सशक्त बनाया गया है।" पीएम मोदी ने कहा कि इस साल 5 अगस्त का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी वर्ष हमारा देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मना रहा है। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रही है। दशकों पहले उन्होंने जो सपना देखा था, वह 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुआ। सप्रधानमंत्री ने 'एक्स' पोस्ट में कहा, "हम जम्मू–कश्मीर और लद्दाख की प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें हासिल करने और 'विकसित भारत' के निर्माण में योगदान देने का अवसर मिले।" बता दें कि 5 अगस्त 2019 को संसद ने अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने को मंजूरी दी थी।

ई–20 विवाद में नितिन गडकरी को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत

मुंबई, (एजेंसी)।केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को ई20 ईंधन विवाद से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने सोशल मीडिया पर प्रसारित गडकरी से संबंधित कथित डीपफेक वीडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई आपत्तिजनक तस्वीरों को तत्काल हटाने का अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह की सामग्री न केवल भ्रामक है बल्कि सार्वजनिक मंचों के लिए पूरी तरह अनुचित भी है। कोर्ट ने आपत्तिजनक कंटेंट पर जताई कड़ी नाराजगी जस्टिस अरिफ डॉक्टर की एकल पीठ ने नितिन गडकरी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिन पोस्ट और वीडियो को हटाने की मांग की गई है, वे पहली नजर में बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक प्रतीत होते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार का कंटेंट सोशल मीडिया जैसे सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसे हर आयु वर्ग के लोग, विशेषकर बच्चे और युवा भी देख सकते हैं। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत के लिए पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है। ई–20 विवाद से जोड़कर बनाए गए थे कथित डीपफेक वीडियो याचिका में कहा गया कि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने ई20 ईंधन नीति को लेकर चल रही।

संसद भवन में पीएम मोदी से मिले राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार

बिहार, (एजेंसी)। राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके कार्यालय कक्ष में शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के विस्तृत ब्योरे की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में उनसे शिष्टाचार भेंट की। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने भी एक्स पर पोस्ट के जरिए मुलाकात की पुष्टि की। पीएमओ ने कहा, "राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने 4 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की।" यह मुलाकात बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल के समाप्त होने के कुछ दिनों बाद हुई है। उन्होंने 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने उन्हें उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई थी।

विपक्ष ने विकास और सामाजिक न्याय के एजेंडे का किया विरोध – सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार को विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष ने अनुपूरक बजट और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सार्थक चर्चा के बजाय व्यवधान पैदा करने का काम किया। राजनीति उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष का लोकतंत्र और विकास विरोधी चेहरा सामने आया है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी का व्यवहार पूरी तरह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक रहा।

उन्होंने आरोप लगाया कि सपा का चरित्र दलित, पिछड़े, किसान, युवा, महिला और गरीब विरोधी है तथा सदन में उसका आचरण लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था। सीएम योगी ने कहा कि सरकार अनुपूरक बजट के माध्यम से शिक्षामित्रों, अनुदेशकों और अन्य अल्प मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों के हितों के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान लेकर आई थी, लेकिन विपक्ष ने उस पर भी चर्चा नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये तथा अनुदेशकों का मानदेय 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये उनकी सरकार ने किया है। इसके साथ ही दोनों वर्गों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों और संतों के स्मारकों, प्रतिमाओं पर छाजन और बाउंड्री वॉल जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी प्रावधान किया गया था। उनका आरोप था कि समाजवादी पार्टी इन जनहितकारी प्रस्तावों को पारित नहीं होने देना चाहती थी, हालांकि सदन ने अंततः अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की सेवा करने वाले अल्प मानदेय प्राप्त कर्मियों का अपमान करना समाजवादी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है।

राहुल गांधी देश को बांटने की राजनीति कर रहे - गौरव भाटिया

नई दिल्ली, (एजेंसी)। जम्मू–कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के सात वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए और इसे भारत की एकता, अखंडता तथा संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक फैसला बताया। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली में प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, जबकि श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा फहराकर इस दिन को विशेष रूप से मनाया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 5 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। सात वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू–कश्मीर को पूरी तरह भारतीय संविधान की मुख्यधारा से जोड़ने का ऐतिहासिक निर्णय

लिया था। उनके अनुसार यह फैसला संविधान की भावना के अनुरूप था और इससे राष्ट्रीय एकता को नई मजबूती मिली। भाटिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए इस ऐतिहासिक निर्णय को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि आज जम्मू–कश्मीर विकास, निवेश, पर्यटन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। श्रीनगर में अनुच्छेद 370 हटने की सातवीं वर्षगांठ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लाल चौक सहित विभिन्न स्थानों पर तिरंगा फहराया। भाजपा कार्यकर्ता मंजूर अहमद ने कहा कि यह उसी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसकी शुरुआत 5 अगस्त 2019 को हुई थी। उन्होंने बताया कि 2019 में भी उन्होंने लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और इस वर्ष भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। उनके अनुसार पार्टी ने प्रत्येक घर, दुकान, संस्थान और सार्वजनिक स्थान पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया है ताकि राष्ट्रीय ध्वज हर स्थान पर सम्मानपूर्वक लहराता दिखाई दे। गौरव भाटिया ने विपक्ष, विशेष रूप से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से नहीं चलने दे रहा है।

दिल्ली सरकार टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध – रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आयोजित जनप्रतिनिधियों के जागरूकता कार्यशाला में हिस्सा लिया और नागरिकों, कॉरपोरेट क्षेत्र तथा सामाजिक संगठनों से इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में शामिल होने की अपील की। भारत राष्ट्रीय समाचार मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए टीबी मरीजों की पहचान और पंजीकरण के लक्ष्यों के मुकाबले दिल्ली ने लगातार अपने वार्षिक लक्ष्य का 95 प्रतिशत से अधिक हासिल किया है। उन्होंने कहा कि टीबी अब पूरी तरह से इलाज योग्य बीमारी है और समय पर जांच तथा पूरा उपचार कराने से मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। यह कार्यक्रम दिल्ली सचिवालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन द्वारा आयोजित किया गया था। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टीबी मुक्त भारत अभियान अब केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं रह गया है, बल्कि जनभागीदारी पर आधारित एक राष्ट्रीय जनआंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने टीबी उन्मूलन को देशव्यापी जन आंदोलन का रूप दिया है और निर्धारित समयसीमा में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष वीडियो प्रदर्शित किया।

महाराष्ट्र दौरे पर टिकैत, किसानों की आत्महत्या पर चिंता

नांदेड़, (एजेंसी)। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने महाराष्ट्र दौरे के दौरान एक बार फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी देने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की फसलों की कीमतों को कानूनी सुरक्षा नहीं मिलेगी, तब तक देश का किसान संतुष्ट नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सहित पूरे देश में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और यही वजह है कि किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। नांदेड़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि किसान संगठन लगातार महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को उठा रहा है। उन्होंने कहा कि नांदेड़ के बाद उनका कार्यक्रम अकोला सहित राज्य के अन्य हिस्सों में भी है। महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल है जहां किसानों की आत्महत्या के मामले सबसे अधिक सामने आते हैं। यहां पैदावार भी कम हो रही है और किसानों को फसलों का उचित दाम भी नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून किसानों की सबसे बड़ी मांग है। जब तक यह कानून लागू नहीं होगा, तब तक किसानों को अपनी उपज औने–पौने दामों पर बेचनी पड़ेगी। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों से इस लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि यह केवल एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों का मुद्दा है। भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि देशभर में तेजी से भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। कई जगह अब भी 2013 के सर्किल रेट के आधार पर मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि कानून के मुताबिक किसानों को सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा मिलना चाहिए। कई स्थानों पर किसानों को केवल दो गुना मुआवजा देकर उनकी जमीन अधिग्रहित की जा रही है।

चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग निर्माण कार्य में लापरवाही मिलने पर डीएम ने अधिशासी अभियंता सहित 13 इंजीनियरों का वेतन रोककर मांगा स्पष्टीकरण

अयोध्या।चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्यों में लापरवाही तथा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर डीएम शशांक त्रिपाठी ने सख्त कार्रवाई किया है।उन्होंने लापरवाही व गुणवत्ता मे कमी पाये जाने को लेकर लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड–3 के 13 अधिकारियों का अगस्त माह का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।साथ ही सभी उन्होंने सभी अधिकारियों को सात दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।बताते चले कि अभी हाल ही में उन्होंने मंडलायुक्त राजेश कुमार के साथ चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग पर निर्माण एवं पौधारोपण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया था।निरीक्षण के दौरान कार्यों में अपेक्षित गुणवत्ता का अभाव, निर्धारित मानकों का पालन न होना तथा अधिकारियों द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण न किए जाने की स्थिति सामने आई।इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए डीएम ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। जैन अधिकारियों पर उन्होंने कार्रवाई किया उनमे अधिशासी अभियंता सत्यपाल सिंह, सहायक अभियंता अखिल वर्मा, विपिन कुशवाहा एवं पूर्ण कुमार रस्तोगी, तथा अवर अभियंता विनोद कुमार, सिद्धार्थ वर्मा, मनोज कुमार श्रीवास्तव,करुणेश कुमार सिंह,प्रवीण कुमार शर्मा, मनोज कुमार,अशोक कुमार यादव,विनोद कुमार विश्वकर्मा एवं स्वतंत्र कुमार बीहड़ का अगस्त माह का वेतन रोक दिया गया है।डीएम शशांक त्रिपाठी ने स्पष्ट कहा कि जनहित एवं धार्मिक महत्व की परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही, उदासीनता अथवा गुणवत्ता से समझौता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें तथा निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता एवं तय मानकों के अनुरूप पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।अन्यथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी।

संपादकीय

आंदोलन पूरी तरह से छात्रों और युवाओं का

नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और सोनम वांगचुक की 26 दिन तक चली भूख हड़ताल की तुलना 2011 के अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से की जा रही है। ऊपर से देखने पर लगेगा कि वैसा ही आंदोलन है। इससे पहले हुए किसी दूसरे आंदोलन से भी इसकी तुलना की जा सकती है। कह सकते हैं कि छात्र और नौजवान वैसे ही उद्वेलित हुआ, जैसे 2012 में निर्भया कांड के समय था। ऊपरी तौर पर इसकी तुलना पिछले पांच दशक में हुए किसी भी दूसरे आंदोलन से की जा सकती है। जेपी के आंदोलन से भी तुलना कर सकते हैं तो मंडल, मंदिर, किसान, शाहीन बाग, पाटीदार या मराठा आंदोलन के कुछ कुछ तत्व इस आंदोलन में भी तलाशे जा सकते हैं। लेकिन थोड़ी बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा कि यह आंदोलन अब तक हुए सभी आंदोलनों से कई मायने में भिन्न है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें किसी तरह की अस्मिता नहीं तलाश सकते हैं। इस लिहाज से यह जेपी और अन्ना हजारे के आंदोलन की तरह है। उन दोनों आंदोलनों में भी समाज का हर वर्ग शामिल था क्योंकि उनमें जिस चीज का विरोध किया जा रहा था वह हर वर्ग को प्रभावित करने वाली थी। बाकी आंदोलनों में किसी न किसी तरह की अस्मिता का मामला रहा है। मंडल से लेकर मराठा या पाटीदार आरक्षण के आंदोलन में जातीय अस्मिता प्रमुख थी। मंदिर आंदोलन में भी हिंदू अस्मिता बहुत मुखर थी तो शाहीन बाग में मुस्लिम अस्मिता। निर्भया कांड के समय हुआ आंदोलन एक फ्लैश प्रोटेस्ट था, जो एक घटना से उपजा था और जल्दी ही समाप्त हो गया। उसका दायरा पूरे देश में नहीं फैला था। इन सबसे उलट नीट यूजी के पेपर लीक के खिलाफ चल रहा आंदोलन पूरी तरह से छात्रों और युवाओं का है। इसमें एक खास बात यह भी है कि कोई एक व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि वह आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। सोनम वांगचुक जरूर इस आंदोलन की नैतिक ताकत हैं लेकिन नेतृत्व उनके हाथ में भी नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी आंदोलन का नेतृत्व करने का दावा नहीं कर सकते हैं। ऐसे आंदोलन के अक्सर अराजक हो जाने का खतरा रहता है। परंतु यह आंदोलन इतना लंबे चलने के बावजूद अराजक नहीं हुआ। जंतर मंतर पर मोटे तौर पर शांति बनी रही। दिल्ली से बाहर दूसरे राज्यों में जरूर कुछ प्रदर्शनों में हिंसा होने की खबरें आईं लेकिन दिल्ली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई के बावजूद शांति रही। इसका कारण यह था कि आंदोलन में असली स्टेकहोल्डर्स शामिल थे। यानी ऐसे छात्र शामिल हुए, जिनको अपना भविष्य बचाना है। वे पेशेवर नेता या प्रदर्शनकारी नहीं थे। छात्र और युवा अपने वास्तविक सरोकारों की वजह से जंतर मंतर पर पहुंचे थे। असल में शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था की गड़बड़ियों के खिलाफ गुस्सा काफी समय से जमा हो रहा था। यह सिर्फ अखिल भारतीय परीक्षाओं जैसे नीट यूजी या जेईई या सीयूईटी आदि का मामला नहीं है। दाखिले और नौकरी के लिए होने वाली राज्यों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी लगातार गड़बड़ी हो रही थी। छात्रों की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि परीक्षाओं का कैलेंडर नहीं बना है। नियमित परीक्षाएं नहीं होती हैं। कई साल की परीक्षाओं को मिला कर एक परीक्षा होती है और उसमें भी पेपर लीक हो जाता है या परीक्षा केंद्र मैनेज करके अलग तरह की धांधली होती है। अगर पेपर लीक या परीक्षा केंद्र मैनेज होने की घटना न हो तो प्रश्न पत्र में गड़बड़ी हो जाती है, उत्तर पुस्तिका जांचने में गड़बड़ी हो जाती है या नतीजे आने में बहुत समय लग जाता है। कई साल की परीक्षा एक साल कराने की वजह से बड़ी संख्या में छात्रों की उम्र सीमा पार हो जाती है। इन सबका संचित गुस्सा जंतर मंतर पर निकला है। शिक्षा और परीक्षा की व्यवस्था में गड़बड़ियों से परेशान एक पूरी पीढ़ी ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया है।

जाति जनगणना - आँकड़ों का प्रश्न या विश्वास की कसौटी?

–लेखक अमृत श्री.

लोकतंत्र में कुछ निर्णय केवल प्रशासनिक नहीं होते, वे समाज की दिशा भी तय करते हैं. जाति जनगणना ऐसा ही एक निर्णय है. यह केवल यह जानने का प्रयास नहीं कि कौन–सी जाति की आबादी कितनी है, बल्कि उस मूल प्रश्न से भी जुड़ा है कि क्या सार्वजनिक नीतियाँ अद्यतन और प्रमाणिक आँकड़ों पर आधारित होनी चाहिए या पुराने अनुमानों के सहारे आगे बढ़ती रहनी चाहिए. केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है. यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में लंबे समय से सभी जातियों की व्यापक गणना नहीं हुई थी. सरकार का मानना है कि इससे समाज की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी और योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से तैयार किया जा सकेगा. यहीं से इस विषय पर बहस शुरू होती है. एक पक्ष का तर्क है कि यदि विकास और सामाजिक न्याय की नीतियाँ तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, तो समाज की वास्तविक संरचना को जानना भी आवश्यक है. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक अवसरों में विभिन्न वर्गों की स्थिति का आकलन अनुमान से नहीं, बल्कि प्रमाणिक आँकड़ों के आधार पर होना चाहिए. दूसरी ओर, कुछ लोगों की आशंका है कि जाति आधारित आँकड़े राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को और अधिक जातीय बना सकते हैं. इससे चुनावी विमर्श में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों की अपेक्षा पहचान की राजनीति अधिक प्रभावी हो सकती है. भारत जैसा विविध और संवेदनशील समाज इस चिंता को पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकता. हालाँकि, वास्तविक चुनौती जनगणना से अधिक उसके बाद इन आँकड़ों के उपयोग की है. आँकड़े स्वयं समाज को नहीं बाँटते, बल्कि उनका उपयोग और प्रस्तुतीकरण यह तय करता है कि वे समाज को जोड़ेंगे या विभाजित करेंगे. यदि उनका उद्देश्य वंचित वर्गों की वास्तविक स्थिति को समझना, संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना और नीतियों को अधिक प्रभावी बनाना होगा, तो उनका महत्व निर्विवाद होगा. लेकिन यदि वे केवल चुनावी रणनीतियों का माध्यम बनकर रह जाएँ, तो उनका मूल उद्देश्य कमजोर पड़ जाएगा. साथ ही यह भी समझना होगा कि आधुनिक भारत की असमानताएँ केवल जाति तक सीमित नहीं हैं. शिक्षा की गुणवत्ता, आय, क्षेत्रीय विषमताएँ, महिलाओं की भागीदारी, डिजिटल पहुँच और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता जैसे अनेक कारक भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. इसलिए किसी भी नीति का आधार बहुआयामी होना चाहिए. जाति एक महत्वपूर्ण संकेतक हो सकती है, लेकिन अकेला आधार नहीं. जाति जनगणना की सफलता इस बात से तय नहीं होगी कि उसमें कितने आँकड़े एकत्र हुए, बल्कि इस बात से होगी कि वे समाज में कितना भरोसा पैदा कर पाए. यदि इन आँकड़ों के आधार पर अधिक न्यायपूर्ण नीतियाँ, बेहतर संसाधन वितरण और समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होता है, तो इसे एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा. इसके विपरीत, यदि यह केवल राजनीतिक बहसों का नया हथियार बनकर रह गई, तो इतिहास इसे एक अधूरे अवसर के रूप में याद करेगा. लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल संख्या में नहीं, बल्कि उस विश्वास में निहित होती है कि प्रत्येक नागरिक की गणना एक आँकड़े के रूप में नहीं, बल्कि समान अधिकार और समान सम्मान वाले नागरिक के रूप में समानताओं के लिए किया जाना चाहिए स

स्थायी वोट बैंक पाला बदलने पर यूँ ही मजबूर नहीं होता

नीरज

राजनीति में कोई भी दल जब किसी क्षेत्र को अपना अभेद्य किला और वहां के मतदाताओं को अपना स्थायी वोट बैंक मानकर निश्चिंत हो जाता है, तभी उसकी पराजय की पटकथा लिखनी शुरू हो जाती है। लोकतंत्र में जनता किसी की बंधक नहीं होती। वह सत्ता देती भी है और उसी सत्ता के अहंकार को ध्वस्त भी करती है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ने इसी लोकतांत्रिक सच को एक बार फिर स्थापित कर दिया है। तीन दशक से अधिक समय तक भाजपा के सबसे सुरक्षित गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत मात्र एक उम्मीदवार की जीत नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक मानसिकता की हार है जो यह मान बैठी थी कि कुछ सीटें और कुछ वोट हमेशा के लिए उसके नाम लिखे जा चुके हैं। बांकीपुर का जनादेश इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी साधारण विधानसभा क्षेत्र का चुनाव नहीं था। यह वही इलाका है जहां मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, विधानसभा, सचिवालय और सत्ता के तमाम केंद्र मौजूद हैं। भाजपा का प्रदेश मुख्यालय भी यहीं है। लंबे समय से यह सीट भाजपा के राजनीतिक वर्चस्व का प्रतीक रही है। ऐसे में यहां मिली हार सिर्फ सीट गंवाने की घटना नहीं, बल्कि सत्ता के आत्मविश्वास पर जनता का करारा प्रहार है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस परिणाम के बाद भाजपा के भीतर भी आत्ममंथन शुरू हो गया है। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि इस चुनाव ने सबसे बड़ा संदेश यह दिया है कि कोर वोट बैंक भी अब स्थायी नहीं रहा। जिस मतदाता को वर्षों तक पार्टी का अटूट समर्थक माना जाता था, उसने इस बार अपना रुख बदलकर बता दिया कि लोकतंत्र में समर्थन किसी दल की जागीर नहीं होता। मतदाता अब काम, व्यवहार और नेतृत्व की शैली के आधार पर फैसला करेगा, न कि केवल पुराने राजनीतिक रिश्तों के आधार पर। यह भी स्वीकार किया जा रहा है कि सत्ता का आत्मविश्वास कई बार अहंकार में बदल जाता है और यही चुनावी हार की सबसे बड़ी वजह बनता है। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह कुछ नेताओं के बयान सामने आए, उन्होंने भी यह संदेश दिया कि पार्टी अपने गढ़ को लेकर अत्यधिक आश्वस्त थी। लेकिन जनता ने मतदान के जरिए यह बता दिया कि किसी भी मतदाता को हल्के में लेने की कीमत राजनीतिक दलों को चुकानी पड़ सकती है। इस हार के पीछे केवल विपक्ष की रणनीति नहीं, बल्कि भाजपा के भीतर की बेचैनी भी चर्चा का विषय बनी। उम्मीदवार चयन से लेकर संगठनात्मक बदलाव तक कई फैसलों को लेकर असंतोष की बातें सामने आईं। राज्य की सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद पार्टी के अंदर जिस तरह की खींचतान दिखाई दी, उसका असर भी चुनावी परिणामों में झलकता नजर आया। यह संदेश भी साफ है कि मजबूत संगठन होने का दावा तभी तक प्रभावी है, जब तक कार्यकर्ता और स्थानीय नेतृत्व स्वयं को सम्मानित महसूस करे। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव ने भी लगभग यही कहानी दोहराई। भाजपा के लिए यह हार केवल कांग्रेस की जीत नहीं थी, बल्कि उसके सबसे प्रभावशाली नेताओं में रहे राज्य के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक प्रभाव पर भी सवाल खड़े कर गई। स्थानीय स्तर पर लंबे समय से चली आ रही गुटबाजी, टिकट वितरण को लेकर नाराजगी और मिश्रा समर्थक संगठनात्मक ढांचे का पूरी तरह सक्रिय न हो पाना भाजपा पर भारी पड़ा। दूसरी ओर कांग्रेस ने स्थानीय असंतोष, बेरोजगारी, पलायन, खाद की कमी और कथित प्रशासनिक दबंगई जैसे मुद्दों को चुनाव का केंद्र बनाया। पार्टी ने चुनाव को सरकार के पक्ष या विपक्ष की लड़ाई बनाने के बजाय स्थानीय जनभावनाओं से जोड़ा और उसी का लाभ उठाया। साफ है कि मतदाताओं ने यहां भी यह संकेत दिया कि किसी एक नेता की राजनीतिक पकड़ या पुराने प्रभाव के भरोसे चुनाव नहीं जीते जा सकते। वहीं बांकीपुर का संदेश केवल भाजपा तक सीमित नहीं है। यह उतनी ही बड़ी चेतावनी राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल (यू) और देश के अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी है। वर्षों से बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों और परंपरागत वोट बैंकों के इर्द–गिर्द घूमती रही है। लेकिन इस उपचुनाव ने संकेत दिया है कि मतदाता अब नए विकल्पों को भी मौका देने के लिए तैयार है। यदि कोई दल यह मानकर चल रहा है कि कोई विशेष जाति, वर्ग या क्षेत्र हमेशा उसके साथ रहेगा, तो बांकीपुर का परिणाम उस भ्रम को तोड़ने के लिए पर्याप्त है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत का महत्व भी केवल एक सीट जीतने तक सीमित नहीं है। इस परिणाम ने यह संकेत दिया है कि बिहार की राजनीति में वर्षों से हावी जातीय ध्रुवीकरण के बीच अब विकास, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और पलायन जैसे मुद्दों के लिए भी राजनीतिक जगह बन रही है। भाजपा के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले शहरी गढ़ में जीत हासिल कर प्रशांत किशोर ने यह साबित किया कि यदि कोई राजनीतिक दल पारंपरिक वोट बैंक की राजनीति से आगे बढ़कर जनता के वास्तविक सरोकारों को लगातार उठाता है, तो वह स्थापित दलों के लिए चुनौती बन सकता है। यह जीत भाजपा के लिए सत्ता के अहंकार के खिलाफ चेतावनी है तो राजद के लिए भी संदेश है कि भाजपा विरोधी राजनीति पर उसका एकाधिकार अब निर्विवाद नहीं रहा। यानी यह परिणाम बिहार की राजनीति में एक नए राजनीतिक विकल्प के उभरने का संकेत भी देता है। यही कारण है कि प्रशांत किशोर की जीत को केवल एक चुनावी सफलता के रूप में नहीं देखा जा रहा। इसे बिहार की राजनीति में एक नए राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में भी देखा जा रहा है। पिछली बार उन्हें चुनावी सफलता भले नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार और पलायन जैसे मुद्दों को राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने का प्रयास किया था। अब बांकीपुर की जीत ने उन मुद्दों को राजनीतिक वैधता भी प्रदान कर दी है। इस जीत का सबसे बड़ा प्रतीकात्मक महत्व यही है कि यह भाजपा के सबसे मजबूत माने जाने वाले शहरी गढ़ में हासिल हुई। इससे यह संकेत भी मिला कि यदि कोई तीसरी राजनीतिक ताकत जनता के बीच विश्वसनीय विकल्प बनती है, तो बिहार की परंपरागत द्विध्रुवीय राजनीति का समीकरण बदल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार इस समय नेतृत्व परिवर्तन और राजनीतिक पुनर्संरचना के दौर से गुजर रहा है।

पीओके की पुकार और दुनिया की जिम्मेदारी

ललित

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में इन दिनों जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं, वे केवल एक चुनावी प्रक्रिया की कहानी नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र, मानवाधिकार और जनविश्वास के गहरे संकट की दास्तान हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की वास्तविक शक्ति निष्पक्ष चुनाव, नागरिक स्वतंत्रता और शासन की जवाबदेही में निहित होती है, लेकिन जब चुनाव भय, हिंसा, प्रशासनिक दबाव और धांधली के आरोपों से घिर जाएँ, तब लोकतंत्र का स्वरूप विकृत हो जाता है। आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति इसी कठोर वास्तविकता की ओर संकेत करती है। वहाँ के लोगों का आक्रोश केवल चुनावी अनियमितताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्षों से चली आ रही आर्थिक उपेक्षा, राजनीतिक भेदभाव और नागरिक अधिकारों की अनदेखी के विरुद्ध भी है। यही कारण है कि वहाँ का असंतोष अब स्थानीय मुद्दा न रहकर अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बनता जा रहा है। लोकतंत्र केवल मतपेटियों तक सीमित नहीं होता। लोकतंत्र का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक बिना किसी भय, दबाव या प्रलोभन के अपनी इच्छा व्यक्त कर सके और उसकी अभिव्यक्ति का सम्मान हो। यदि किसी क्षेत्र में चुनाव पहले से तय परिणामों का माध्यम बन जाएँ, यदि सत्ता का पूरा तंत्र एक दल विशेष के पक्ष में खड़ा दिखाई दे, यदि विरोध की आवाज को बलपूर्वक दबाया जाए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, तो उसे लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में समय–समय पर ऐसे आरोप सामने आते रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सत्ता का प्रभाव प्रशासन और चुनावी व्यवस्था पर स्पष्ट दिखाई देता है। यदि जनता के मन में यह विश्वास ही समाप्त हो जाए कि उसका मत परिवर्तन ला सकता है, तो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार ही समाप्त हो जाता है। पाकिस्तान स्वयं को लोकतांत्रिक राष्ट्र कहता है, लेकिन उसके व्यवहार में लोकतंत्र की मूल भावना बार–बार प्रश्नों के घेरे में आ जाती है। लोकतंत्र का अर्थ केवल चुनाव करवा देना नहीं है, बल्कि असहमति का सम्मान करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना और सत्ता की आलोचना को स्वीकार करना भी है। यदि विरोध करने वालों को राष्ट्रविरोधी या व्यवस्था विरोधी बताकर दबाने का प्रयास किया जाए, यदि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित कर दी जाए और यदि प्रशासन जनता के बजाय सत्ता के हितों की रक्षा करता दिखाई दे, तो लोकतांत्रिक मूल्यों की विश्वसनीयता स्वतः समाप्त होने लगती है। पाकिस्तान की यही दोहरी नीति आज उसके लोकतांत्रिक दावों पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक भी है। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद वहाँ का सामान्य नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। बिजली संकट, महँगाई, बेरोजगारी, आवश्यक वस्तुओं की कमी और विकास की धीमी गति ने जनजीवन को अत्यंत कठिन बना दिया है। यह विडंबना है कि जिन नदियों से ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी क्षेत्र के लोग लंबे समय तक बिजली कटौती झेलने को विवश हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके संसाधनों का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन उनके विकास के लिए अपेक्षित निवेश नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में जनता के भीतर असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक है। लोकतांत्रिक शासन की सबसे बड़ी कसौटी यह होती है कि वह संकट के समय जनता के साथ किस प्रकार खड़ा रहता है। यदि जनता की शिकायतों का समाधान संवाद से करने के बजाय दमन से किया जाए, तो यह शासन की कमजोरी का प्रमाण होता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों और असंतोष के प्रति जिस प्रकार का रवैया अपनाए जाने के आरोप लगते रहे हैं, वे चिंता पैदा करते हैं। लोकतंत्र का उत्तर हिंसा नहीं, बल्कि संवाद होता है। दुर्भाग्य से जब शासन संवाद छोड़कर शक्ति प्रदर्शन का मार्ग अपनाता है, तब जनता और व्यवस्था के बीच विश्वास की खाई और गहरी हो जाती है। विश्व समुदाय के सामने भी यह एक गंभीर नैतिक प्रश्न है। यदि लोकतंत्र और मानवाधिकार वास्तव में सार्वभौमिक मूल्य हैं, तो उनका संरक्षण केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ और महाशक्तियाँ अनेक अवसरों पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मानवाधिकारों और लोकतंत्र की रक्षा की बात करती हैं। यदि यही सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में उठ रहे प्रश्नों की भी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। मानवाधिकारों का मूल्य भौगोलिक सीमाओं से निर्धारित नहीं होता। जहाँ भी नागरिकों की स्वतंत्रता और सम्मान प्रभावित होता है, वहाँ वैश्विक समुदाय की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह स्थिति पर गंभीरता से ध्यान दे। भारत ने हाल की घटनाओं के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की स्थिति की ओर आकर्षित किया है और वहाँ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा दमन रोकने की आवश्यकता पर बल दिया है। इस प्रकार की अपील को केवल कूटनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। यदि किसी क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया पर लगातार प्रश्न उठ रहे हों, यदि नागरिक असुरक्षा और अविश्वास के वातावरण में जी रहे हों और यदि उनके मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हों, तो विश्व समुदाय की निष्क्रियता भविष्य के लिए और भी गंभीर संकट उत्पन्न कर सकती है। पाकिस्तान की लोकतांत्रिक नीतियों का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि एक ओर वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लोकतंत्र, न्याय और जनाधिकारों की बात करता है, वहीं दूसरी ओर अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में उन्हीं मूल्यों को व्यवहार में उतारने में विफल दिखाई देता है। लोकतंत्र की विश्वसनीयता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि शासन की कार्यशैली से सिद्ध होती है। यदि नागरिक स्वयं को उपेक्षित, असुरक्षित और असहाय महसूस करें, तो लोकतंत्र का दावा खोखला प्रतीत होने लगता है। लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ सत्ता परिवर्तन की संभावना, स्वतंत्र संस्थाएँ, निष्पक्ष प्रशासन और नागरिकों की गरिमा की रक्षा है। यदि ये तत्व अनुपस्थित हों, तो चुनाव केवल औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में संपन्न हों। मतदाता बिना किसी भय या दबाव के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, राजनीतिक दल समान अवसर प्राप्त करें और चुनावी प्रक्रिया पर जनता का विश्वास पुनर्स्थापित हो।

नीलेकणी के ऊपर परीक्षा प्रणाली में सुधार का जिम्मा

अजीत द्विवेदी

इंफोसिस के सह संस्थापक और भारत में आधार क्रांति के सूत्रधार नंदन नीलेकणी के ऊपर केंद्र सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देने का जिम्मा सौंपा है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के पूर्व प्रमुख एस सोमनाथ को भी इस उच्चाधिकार प्राप्त कमेटी का सदस्य बनाया गया है। पता नहीं लोगों को याद हो कि न हो, दो साल पहले इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। जैसे 2026 में नीट यूजी पेपर लीक के बाद यह कमेटी बनी है वैसे ही 2024 में नीट यूजी पेपर लीक के बाद वह कमेटी बनी थी। राधाकृष्ण कमेटी ने एक सौ ज्यादा सिफारिशें की थीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी 27 सिफारिशें ऐसी हैं, जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। कुछ सिफारिशें आंशिक तौर पर मानी गईं और 57 सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार किया गया। लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? दो साल के बाद फिर पेपर लीक हो गया! राधाकृष्ण कमेटी ने सिफारिश की थी नीट यूजी सहित करीब 20 प्रतियोगिता परीक्षाएं कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में विषय के विशेषज्ञों को शामिल किया जाए। इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद भी पेपर लीक होना जारी है और दूसरी गड़बड़ियां भी हो ही रही हैं तो इसका अर्थ है कि एकमात्र समस्या यह नहीं है कि एनटीए में विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं। समस्या संरचनात्मक और व्यवस्थागत है। अगर नंदन नीलेकणी संरचनात्मक समस्याओं को समझ कर उसे ठीक करने का सुझाव देते हैं तब तो ठीक है अन्यथा इसका भी कोई मतलब नहीं होगा। उनके सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती यह है कि क्या वे अखिल भारतीय परीक्षा के सिद्धांत को खत्म करने की सिफारिश करेंगे? क्या वे कहेंगे कि एक बार में 24 लाख छात्रों वाली नीट यूजी की परीक्षा नहीं होनी चाहिए? क्या वे यह सिफारिश कर सकते हैं कि मेडिकल में दाखिले की पुरानी व्यवस्था बहाल हो और नीट यूजी की बजाय राज्यों को अपने कॉलेजों में दाखिले का अधिकार पहले जैसा दिया जाए? यानी शिक्षा और परीक्षा के मामले में राज्यों की स्वायत्तता सुनिश्चित की जाए। अगर नंदन नीलेकणी की कमेटी नीट समाप्त करने और मेडिकल में दाखिले की परीक्षा का विकेंद्रीकरण करने की सिफारिश नहीं करती है तो उनकी सिफारिशों का स्कोप बहुत सीमित हो जाएगा और तब किसी बड़े सुधार की संभावना कम हो जाएगी। अब सवाल है कि अगर नीट समाप्त करने या नीट जैसी दूसरी अखिल भारतीय परीक्षाएं खत्म करने की सिफारिश नीलेकणी कमेटी नहीं करती है तो उसके पास क्या विकल्प बचेगा? सबसे अच्छा तो यही होगा कि नीट को समाप्त किया जाए। लेकिन अगर सरकार की ओर से कमेटी की सिफारिशों का जो स्कोप तय किया जाएगा यानी जो फ्रेमवर्क दिया जाएगा उसमें पहले ही यह स्पष्ट कर दिया जाए कि नीट की परीक्षा जारी रहेगी तो फिर नीलेकणी कमेटी को नीट को इंजीनियरिंग में दाखिले की परीक्षा जेईई की तरह दो चरणों में कराने की सिफारिश करनी चाहिए। ध्यान रहे अगले साल नीट की परीक्षा जेईई की तरह कंप्यूटर आधारित होगी और कई पालियों में होगी। हालांकि उसमें प्रश्नपत्रों की कठिनता के आधार पर अंकों के सामान्यीकरण की अलग समस्या आती है। फिर भी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा पेपर लीक की संभावना को कम करती है। इसके साथ साथ अगर नीट की परीक्षा भी जेईई के तरह दो चरण में हो तो पेपर लीक की संभावना और कम हो सकती है। दो चरण का अर्थ है कि पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा हो और दूसरे चरण में एडवांस परीक्षा हो। पहले चरण में मल्टीपल च्वाइस वाले प्रश्न हों और दूसरे चरण में सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएं। इसके अलावा नीलेकणी कमेटी को मेडिकल की पढ़ाई की फीस को नियमित करने के बारे में भी सुझाव देने चाहिए। अभी मेडिकल की परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न पत्र इसलिए लीक होते हैं कि एक बार में परीक्षा होती है और 720 अंकों की परीक्षा में अगर अच्छे अंक आ गए तो देश के प्रीमियम संस्थान में बहुत कम फीस में पढ़ने का मौका मिलता है। अन्यथा निजी कॉलेजों में फीस इतनी ज्यादा है कि लोग स्वाभाविक रूप से पेपर लीक पर पैसा खर्च करने के लिए प्रेरित होते हैं। खुद सरकार इसी वजह से इसे हाई स्टेक यानी बड़े दांव वाली परीक्षा मानती है। नीट के बचाव में तर्क दिया जाता है कि इसमें क्वालिफाई करके गरीब बच्चे भी मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। यह गलत है। निजी मेडिकल कॉलेजों में फीस एक से डेढ़ करोड़ रुपए तक है। ऐसे में कौन गरीब अपने बच्चों को वहां पढ़ा पाएगा! अगर डोनेशन नहीं देना पड़े तब भी निजी कॉलेजों में मेडिकल की पढ़ाई का खर्च सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर है। बहरहाल, नीलेकणी कमेटी को सिर्फ नीट पर विचार नहीं करना है, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के सुझाव देने हैं। इसकी शुरुआत एनटीए से हो सकती है। भारत सरकार ने एक देश, एक परीक्षा की महत्वाकांक्षी योजना के तहत एनटीए का गठन किया। इसके बाद एक एक करके परीक्षाओं को अखिल भारतीय स्वरूप दिया जाने लगा। मेडिकल की परीक्षा के साथ साथ केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए भी सीयूईटी की परीक्षा ली जाने लगी। इसमें अलग समस्याएं हैं। वास्तविकता यह है कि एनटीए देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार में शून्य योगदान दे रहा है। सो, नीलेकणी कमेटी एनटीए को खत्म करने और पुरानी विकेंद्रित परीक्षा व्यवस्था बहाल करने की सिफारिश करे। सवाल है कि अगर एनटीए को समाप्त करना उसके स्कोप ऑफ वर्क से बाहर हो तो क्या करना चाहिए? तब उसे एनटीए में सुधार की सिफारिश करनी चाहिए। सबसे पहला सुधार तो यह जरूरी है कि एनटीए को कम से कम वैधानिक दर्जा दिया जाए। अगर सरकार चाहती है कि यूपीएससी की तरह इसकी परीक्षाएं विश्वसनीय बनें तो इसे संवैधानिक नहीं तो वैधानिक दर्जा दिया जाए। इसका अपना कैडर बने ताकि तदर्थ ढंग से काम नहीं हो। अभी इधर उधर से ले आकर अधिकारियों को रखा जाता है और गड़बड़ी होने पर बाद में उनको वापस अपने कैडर में भेज दिया जाता है। इससे जवाबदेही नहीं बनती है। इसके बाद ठेके पर नियुक्ति रोकने की सिफारिश की जाए और परीक्षा से जुड़े काम आउटसोर्स करने पर रोक लगे। यूपीएससी की तरह एनटीए का अपना बुनियादी ढांचा बने। विशेषज्ञों की नियुक्ति हो और पूरे साल इसका काम चले। जैसे यूपीएससी की परीक्षा में प्रश्न पत्र के ढेर सारे सेट बनते हैं और किसी को पता नहीं होता है कि परीक्षा में कौन से सेट का इस्तेमाल होगा वैसी व्यवस्था एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए भी की जाए। एनटीए जिन परीक्षाओं का आयोजन करता है उसके अलावा भी कई एजेंसियां हैं, जो दाखिला और भर्ती परीक्षा आयोजित करती हैं। उनमें भी एनटीए की तर्ज पर ही सुधार की सिफारिश होनी चाहिए। हालांकि सिर्फ कमेटी की सिफारिशों से कुछ खास नहीं होगा। सरकार की मंशा और राजनीतिक इच्छाशक्ति भी होनी चाहिए तभी जरूरी सुधार होंगे।

फसलों की सुरक्षा कवच है फसल बीमा योजना '31 अगस्त तक कराएं खरीफ फसलों का बीमा

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जलवायु परिवर्तन के दौर में प्रकृति की मार से फसलों में होने वाली क्षति से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बचाएगी। जनपद में खरीफ मौसम की सात फसलों का बीमा किया जा रहा है, इसके लिए किसानों को दो प्रतिशत मामूली प्रीमियम देना होगा। बीमा की जिम्मेदारी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सौंपी गई है। पहले कर्ज से उगाई गई फसलों का खुद बीमा हो जाता था, किंतु अब योजना को ऐच्छिक कर दी गई है। कृषकों के लिए 31 अगस्त तक की तिथि निर्धारित की गई है। ाकृतिक आपदाओं से फसलों के नुकसान होने पर किसानों के आर्थिक क्षति की भरपाई करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू किया है। जनपद में खरीफ की धान, मक्का, उर्द, बाजरा, ज्वार, तिल और अरहर की फसल का बीमा किया जाएगा, इसके लिए किसानों को प्रीमियम का मात्र दो प्रतिशत का भुगतान करना होगा, बाकी धनराशि सरकार द्वारा दी जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर बीमा का लाभ – अधिसूचित क्षेत्रों में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाने, असफल बुवाई की स्थिति फसल की बुवाई से कटाई के समयावधि में प्राकृतिक आपदाओं सूखा, बाढ़, जल प्लावन, ओला, भूस्खलन, आकाशी बिजली से आग, तूफान चक्रवात, रोगों, कीटों आदि से खड़ी फसल नष्ट होने पर बीमा का लाभ मिलता है। व्यक्तिगत फसल बीमा का लाभ – ओलावृष्टि, भूस्खलन, जल प्लावन तथा फसल की कटाई के बाद आगामी 14 दिनों तक खेत में सूखने के लिए रखी गई फसल की क्षति पर बीमा का लाभ मिलेगा। किसानों को क्षति के 72 घंटे के अंदर संबंधित बैंक, बीमा कंपनी, कृषि विभाग को सूचना देना होगा। उप परियोजना निदेशक आत्मा डा. रमेश चंद्र यादव ने बताया कि खरीफ 2026 मौसम हेतु बीमा कराने की अन्तिम तिथि ऋणी कृषकों के लिए 31 अगस्त तथा गैर ऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त निर्धारित है, एनसीआईपी पोर्टल फसल बीमा हेतु खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आध ारित फसल बीमा योजना में शामिल न होने वाले ऋणी किसानों को संबंधि त बैंकों में लिखित सूचना देना होगा अन्यथा उनके खाते से प्रीमियम कटौती कर योजना से जोड़ दिया जाएगा। गैर ऋणी कृषक सीएससी से अपनी फसलों का बीमा करा सकते है, उन्होंने बताया कि वर्षात कम होने से उत्पादन घटना स्वाभाविक है ऐसे में अधिक से अधिक किसान अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराए ताकि नुकसान की भरपाई फसलबीमा योजनान्तर्गत हो सकें। फसल, बीमित राशिध्हे0, कृषक अंश – धान, 79800, 1596 रु0, मक्का, 35000, 700 रु0, बाजरा, 31900, 638 रु0, ज्वार, 58000, 1160 रु0, उर्द, 71900, 1438 रु0, अरहर, 85500, 1710 रु0, तिल, 23100, 462 रुपये।

सई नदी में युवती ने लगाई छलांग लाश बरामद, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर स्थित सिकरारा थाना क्षेत्र स्थित बरगुदर पुल से बुधवार सुबह सई नदी में 19 वर्षीय युवती के छलांग लगाने की आशंका के बाद पुलिस और स्थानीय गोताखोरों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटनास्थल पर युवती की साइकिल और चप्पल मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। डीह जहाँनिया गांव निवासी मुन्ना लाल प्रजापति की पुत्री श्वेता प्रजापति (19) के सई नदी में कूदने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण बरगुदर पुल पर पहुंच गए। पुल पर उसकी साइकिल और चप्पल मिली, जिसके आधार पर नदी में छलांग लगाने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही सिकरारा थानाध्यक्ष विश्वनाथ प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद स्थानीय गोताखोरों एवं ग्रामीणों की मदद से सई नदी में व्यापक खोज अभियान शुरू कराया गया। नदी के दोनों किनारों पर भी तलाशी ली जा रही है। ग्राम प्रधान जितेंद्र यादव भी मौके पर मौजूद रहे और पुलिस–प्रशासन के साथ राहत एवं खोज अभियान में सहयोग किया। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी युवती की तलाश में जुटे हुए हैं। मौके पर पहुंचे थानाध यक्ष का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला नदी में छलांग लगाने का प्रतीत हो रहा है, हालांकि घटना के वास्तविक कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। परिजनों एवं आसपास के लोगों से पूछताछ कर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस, गोताखोरों और ग्रामीणों की संयुक्त टीम लगातार सई नदी में तलाश अभियान चलाया काफी देर बाद लड़की का शव बरामद कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

बरसात में बढ़ सकता है जोड़ों और कमर का दर्द, फिजियोथेरेपी से करें बचाव

आर एल पाण्डेय

लखनऊ। गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉ. ओमजी तिवारी ने बताया कि मानसून के मौसम में बढ़ी हुई नमी के कारण कमर दर्द, गर्दन में अकड़न, घुटनों का दर्द और मांसपेशियों में जकड़न

जैसी समस्याएँ बढ़ जाती हैं। विशेषकर बुजुर्गों, गठिया के मरीजों तथा लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले लोगों को इस मौसम में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। डॉ. ओमजी तिवारी ने बताया कि नियमित व्यायाम, हल्की स्ट्रेचिंग, सही शारीरिक मुद्रा और समय पर फिजियोथेरेपी से इन समस्याओं से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। दर्द को लंबे समय तक नजरअंदाज करना उचित नहीं है। यदि दर्द लगातार बना रहे, सूजन हो या चलने–फिरने में कठिनाई महसूस हो, तो जल्द से जल्द फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। फिजियोथेरेपी न केवल दर्द से राहत दिलाती है, बल्कि मांसपेशियों की ताकत, जोड़ों की गतिशीलता और शरीर की कार्यक्षमता में भी सुधार करती है। स्वस्थ जीवनशैली और नियमित शारीरिक गतिविधि अपनाकर मानसून के मौसम में भी स्वयं को सक्रिय और स्वस्थ रखा जा सकता है।

एलएलएम छात्र ने डिग्री जारी न होने पर राज्यपाल से लगाई न्याय की गुहार

लखनऊ, (संवाददाता)। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली के विधि विभाग के एलएलएम अंतिम वर्ष के छात्र पवन कुमार ने डिग्री जारी न किए जाने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर न्याय की मांग की है। सोमवार को लखनऊ पहुंचे पवन कुमार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल से मुलाकात का प्रयास किया। मुलाकात नहीं हो पाने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत कर विश्वविद्यालय प्रशासन और विधि विभाग की एक प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए।पवन कुमार का कहना है कि कुछ दिन पहले भी उन्होंने लखनऊ आकर अपनी समस्या सार्वजनिक की थी, लेकिन समाचार प्रसारित होने के बावजूद अब तक उनकी डिग्री जारी नहीं की गई।

राज्यमंत्री गिरीश के प्रयास से 7 मरीजों को मिली 7.20 लाख की सहायता मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से अस्पतालों में भेजी गई सहायता

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल एवं युवा कल्याण विभाग गिरीश चंद्र यादव के प्रयास से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से जनपद के सात जरूरतमंद मरीजों को उपचार के लिए कुल 7 लाख 20 हजार 150 रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि यह धनराशि संबंधित चिकित्सा संस्थानों को उपचार के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि स्वीकृत लाभार्थियों में बंजारेपुर की इन्द्रावती देवी को बीएचयू के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए 1 लाख रुपये, शेखपुर सुतौली निवासी शैलेन्द्र यादव को केजीएमयूधगांधी मेमोरियल एंड एसोसिएट हॉस्पिटल के लिए 1 लाख रुपये, पाल्हामऊ खुर्द निवासी रामकिशुन पाल को बीएचयू के लिए 95 हजार 150 रुपये, डेरामुआयना (कुरचनपुर) निवासी रतना देवी को बीएचयू के लिए 1 लाख रुपये, शेखपुर अशरफपुर निवासी रामजीत यादव को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये, वाजिदपुर उत्तरी निवासी निखिल राय को बीएचयू के लिए 1 लाख रुपये तथा गरोठन निवासी सविता को डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के लिए 75 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत की गई है। राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से स्वीकृत कुल 7 लाख 20 हजार 150 रुपये की राशि संबंधित अस्पतालों को मरीजों के उपचार के लिए संबंधित अस्पतालों में उपलब्ध ा कराई गई है, जिससे जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यालय में आने वाले किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों की योगी सरकार पूरा सहयोग कर रही है। हमारी सरकार गरीबों, मजलूमों और जरूरतमंदों की सरकार है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सबका साथ, सबका विकास के तर्ज पर सभी की सहायता की जा रही है। मरीजों के परिजनों ने राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव और प्रदेश की योगी सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है।

खाद बदलने के विवाद में किसान से मारपीट का आरोप, डीएम से लगाई न्याय की गुहार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में तेजीबाजार थाना क्षेत्र स्थित हैदरपुर की चितौड़ी सहकारी समिति में खाद बदलने को लेकर हुए विवाद में एक किसान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने बुधवार को जिलाधिकारी को प्रार्थना–पत्र देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है। मामले में तेजीबाजार थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पीड़ित किसान भरत विश्वकर्मा का आरोप है कि वह तीन अगस्त को चितौड़ी सहकारी समिति से खाद लेने गए थे। इस दौरान उन्हें फटी हुई और सीलनयुक्त खाद की बोरियां दी गईं। जब उन्होंने खाद बदलने का अनुरोध ा किया तो समिति के सचिव संतोष सिंह और राजेंद्र प्रसाद सिंह ने उनके साथ अभद्रता करते हुए गाली–गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। किसान का आरोप है कि विरोध ा करने पर दोनों आरोपित उन्हें खींचकर एक घर में ले गए, जहां रॉड, लाठी और डंडों से मारपीट की गई। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने बीच–बचाव कर उनकी जान बचाई। भरत विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद अभी तक किसी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ित ने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई तथा अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की है।इस मामले में जानकारी लेने पर क्षेत्राधिकारी सदर परमानन्द कुशवाहा ने कहा कहना है कि दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

पं. जनेश्वर मिश्र के विचारों पर चलकर 2027 में सपा सरकार बनाने का लिया संकल्प - राकेश मौर्य

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी जौनपुर ने बुधवार को पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व राज्यसभा सांसद पंडित जनेश्वर मिश्र की 94वीं जयंती जिला कार्यालय में श्रद्धापूर्वक मनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने की। इस अवसर पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पं. जनेश्वर मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद आयोजित गोष्ठी का संचालन जिला महासचिव आरिफ हबीब ने किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य ने कहा कि पं. जनेश्वर मिश्र समाजवादी विचारधारा के प्रखर चिंतक, संघर्षशील नेता तथा गरीबों, किसानों, मजदूरों और वंचित वर्ग की सशक्त आवाज थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सामाजिक न्याय और समाजवादी मूल्यों के लिए समर्पित किया। उनके विचार आज भी समाजवादियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि उनके आदर्शों को जन–जन तक पहुंचाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान उपस्थित नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पं. जनेश्वर मिश्र के विचारों पर चलने तथा वर्ष 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने और अखिलेश यादव को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को पूर्व विधायक लालबहादुर यादव, मोहम्मद अरशद खान, डॉ. अवध नाथ पाल, हिसामुद्दीन शाह, रमापति यादव सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। अंत में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामलाल पाल के परिजन सहित अन्य दिवंगत लोगों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

जौनपुर पुलिस को मिला हाईटेक इंटरसेप्टर कैमरा, एक किलोमीटर दूर से ओवरस्पीड वाहनों का कटेगा ई–चालान

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जौनपुर पुलिस को यातायात प्रबंधन और अपराध नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक इंटरसेप्टर कैमरा उपलब्ध कराया गया है। यह हाईटेक कैमरा हाईवे पर एक किलोमीटर की दूरी से ही ओवरस्पीड वाहनों की पहचान कर उनका स्वतः ई–चालान करने में सक्षम है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने वैन युक्त कैमरे को हरि झंडी दिखाकर पुलिस लाइन से रवाना किया। अपर पुलिस अध ीक्षक (ग्रामीण) आतिश कुमार सिंह ने बताया कि नई तकनीक से लैस यह इंटरसेप्टर कैमरा सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के साथ–साथ अपराध नियंत्रण में भी प्रभावी भूमिका निभाएगा। इसके माध्यम से संदिग्ध वाहनों की पहचान, अवैध गतिविधि ायों की निगरानी तथा हाईवे पर अपराधियों की धरपकड़ में पुलिस को मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि कैमरा निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार से चलने वाले वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेगा और संबंधित वाहन का ई–चालान स्वतः जारी किया जा सकेगा। इससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि इंटरसेप्टर कैमरे के संचालन से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने के साथ कानून व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। साथ ही हाईवे पर निगरानी और अधिक प्रभावी होगी तथा नियम तोड़ने वालों के लिए बच निकलना आसान नहीं रहेगा। पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा का पालन करने और यातायात नियमों का सम्मान करने की अपील की है, ताकि सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

हर घर तिरंगा केवल एक अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति का जनोत्सव है – आकांक्षा सोनकर

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले श्हर घर तिरंगाश अभियान को जन–आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अभियान की रूपरेखा, तिरंगा वितरण, तिरंगा यात्राओं तथा जनजागरण कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री आकांक्षा सोनकर, विशिष्ट अतिथि पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील उपाध्याय तथा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि आकांक्षा सोनकर ने कहा कि श्हर घर तिरंगाश केवल एक अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति का जनोत्सव है। तिरंगा देश की राष्ट्रीय अस्मिता, एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर घर तक तिरंगा पहुंचाने तथा अधिक से अधिक लोगों को तिरंगा यात्रा से जोड़ने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि सुशील उपाध्याय ने कहा कि यह अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को स्मरण करने का अवसर है। तिरंगा यात्रा के माध्यम से युवाओं, विद्यार्थियों और समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़कर राष्ट्रीय एकता का संदेश जन–जन तक पहुंचाया जाना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति ने कहा कि जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता अभियान की सफलता के लिए पूरी निष्ठा से जुटा है। बूथ, शक्ति केंद्र और मंडल स्तर पर तिरंगा यात्राएं, प्रभात फेरियां तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यह अभियान राष्ट्रीय चेतना का पर्व बन चुका है और लक्ष्य है कि जनपद का कोई भी घर तिरंगे से वंचित न रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री संदीप तिवारी ने किया। कार्यशाला में पार्टी के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

ओमेक्स सिटी चोरी कांड का खुलासा, फरार शातिर चोर गिरफ्तार जेवरात और नकदी बरामद

लखनऊ, (संवाददाता)।राजधानी के बिजनौर थाना क्षेत्र स्थित ओमेक्स सिटी में बंद मकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए फरार चल रहे एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए जेवरात और नकदी बरामद की गई है। मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था।पुलिस आयुक्त तरुण गाबा और संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी मो. मुश्ताक के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस उपायुक्त रल्लापल्ली वसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर अभिषेक कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कपिल गौतम के नेतृत्व में गठित टीम ने यह सफलता हासिल की।पुलिस के अनुसार 19 जुलाई 2026 को ओमेक्स सिटी निवासी गर्विता सिंह ने अपने बंद मकान का ताला तोड़कर जेवरात, नकदी और अन्य कीमती सामान चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस संबंध में बिजनौर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को 22 जुलाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि उसके साथी की तलाश जारी थी।फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित पुलिस टीमों ने करीब 70 से 80 सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया। इसी क्रम में 2 अगस्त को शंकर कुमार शाक्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद कर लिया गया। बाद में उसे न्यायालय में पेश किया गया।पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने साथी सुनील उर्फ रंजीत के साथ मिलकर 18 और 19 जुलाई की रात बंद पड़े मकान की रेकी करने के बाद ताला तोड़कर घर में प्रवेश किया था। दोनों ने मिलकर जेवरात, घड़ी, सिक्के, लॉकर की चाबी और नकदी चोरी की थी। आरोपी ने स्वीकार किया कि बरामद किए गए जेवरात चोरी के ही हैं और वह उन्हें बेचने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया।पुलिस के अनुसार आरोपी और उसका साथी रात के समय बंद पड़े मकानों की रेकी कर ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और बाद में चोरी का सामान बेचकर रकम आपस में बांट लेते थे।गिरफ्तार आरोपी की पहचान शंकर कुमार शाक्य निवासी रजनीखंड, शारदा नगर, थाना आशियाना, लखनऊ (मूल निवासी इमराहिमपुर, बाराबंकी) के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस अधिनियम और अन्य मामलों में मुकदमे दर्ज हैं।पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक सोने की चेन, दो जोड़ी कान के टॉप्स, एक नोज पिन, दो कड़े, एक जोड़ी पायल तथा 5,230 रुपये नकद बरामद किए हैं।

कैंसर संस्थान में मरीजों को मिलेंगी नई सुविधाएं

लखनऊ, (संवाददाता)। कल्याण सिंह कैंसर संस्थान में डिजिटल पीईटी–सीटी स्कैन, साइबरनाइफ जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं जल्द शुरू होंगी। इससे कैंसर की समय पर और सटीक पहचान हो सकेगी। बीमारी की सही स्टेज का पता लगाने में मदद मिलेगी। बिना बड़े ऑपरेशन के कई जटिल मरीजों का इलाज संभव होगा। इसे लेकर सोमवार का को अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा अमित कुमार घोष व सचिव नेहा शर्मा ने कैंसर संस्थान का निरीक्षण किया। अपर मुख्य सचिव ने न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग, साइबरनाइफ सिस्टम, ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम और निर्माणाधीन टोमोथेरेपी परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा कर मरीजों के लिए जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने कहा कि पीईटी–सीटी, साइबरनाइफ और टोमोथेरेपी जैसी

सुविधाएं शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश के कैंसर मरीजों को प्रदेश में ही विश्वस्तरीय, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध इलाज मिल सकेगा। संस्थान के निदेशक डॉ. एमएलबी भट्ट ने बताया कि डिजिटल पीईटी–सीटी स्कैन शुरू होने से मरीजों को कैंसर की सटीक जांच होगी। इससे बीमारी की पहचान, स्टेजिंग, इलाज के प्रभाव और दोबारा कैंसर होने की समय रहते जानकारी देने में मदद करेगी। पीपीपी मॉडल पर निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। साइबरनाइफ परियोजना का कार्य पूरा हो चुका है।

प्रदेश के चार हजार स्कूलों के ऊपर से गईं हाईटेंशन लाइन, हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब

लखनऊ, (संवाददाता)। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के करीब चार हजार स्कूलों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन बिजली लाइनों को बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने पॉवर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक को मामले में पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता को आदेश दिया कि सक्षम प्राधिकारी को इस आदेश की सूचना देकर अगली सुनवाई तक इस संबंध में उनका जवाब पेश करें। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश गोमती रिवर बैंक रेजिडेंट्स

वेलफेयर एसोसिएशन की जनहित याचिका पर दिया। न्यायमित्र ने अदालत को बताया कि कई मामलों में हाईटेंशन लाइनें स्कूल परिसरों पर गिर चुकी हैं जिससे बच्चों की जान खतरे में पड़ी। इस संबंध में किए गए अध्ययन और अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया।

महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला ने उप निरीक्षक सोनी के साथ महिलाओ व बालिकाओं को सुरक्षा के प्रति किया जागरूक

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। बुधवार को एसएसपी डॉ गौरव ग्रोवर तथा मिशन शक्ति फेज 5 के नोडल प्रभारी व एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी के निर्देश पर सीओ सिटी श्रीयेश त्रिपाठी की देखरेख मे महिला थानाध्यक्ष आशा शुक्ला के नेतृत्व मे उप निरीक्षक सोनी ने मिशन शक्ति अभियान के तहत जिला व महिला चिकित्सालय के अलावा शहर के विभिन्न कॉलेज और चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाया।उन्होंने कॉलेज तथा चौक सहित अन्य प्रमुख चौराहों पर छात्राओं व महिलाओ को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रति जागरूक किया।इस मौके पर उन्होंने मिशन शक्ति अभियान फेज फाइव के तहत सुरक्षात्मक उपाय भी बताई।इस मौके पर उन्होंने महिलाओं तथा बालिकाओं को सुरक्षात्मक टिप्स की भी जानकारी देते हुए बताया कि जिससे कभी भी संकट के समय आप अपनी सुरक्षा कर सकती हैं।इस मौके पर उन्होंने महिलाओ व बालिकाओं से कहीं।उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए जहां एक तरफ उनके विकास को लेकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिला सशक्तिकरण सुकन्या समृद्धि योजना सहित एक से बढ़कर एक कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं चल रही हैं।इस मौके पर उन्होंने वहां पर मौजूद बालिकाओं को पंपलेट व बैनर पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना का अंदेशा हो तो बिना झिझक अपने नजदीकी पुलिस कर्मियों, महिला थाना तथा अपने परिजनों को फोन पर बताये।इस मौके पर उन्होंने विधवा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं जिसमे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं सुकन्या समृद्धि योजना और हेल्पलाइन नंबर के बारे में महिलाओं को जागरूक किया।इसके अलावा उन्होंने उन्हें किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता हेतु विमेन पावर लाइन 1090, यूपी 112, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड लाइन 1098, साइबर अपराध 1930 के बारे में बताया गया।बताया कि यह सभी नंबर आप लोग हमेशा याद रखें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत हो तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं।

टूटते रिश्तों को जोड़ने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही महिला थानाध्यक्ष बाराबंकी कुमारी रत्ना

अयोध्या।पुलिस की भूमिका केवल अपराध नियंत्रण तक सीमित नहीं है,बल्कि समाज में विश्वास, सुरक्षा और पारिवारिक सौहार्द स्थापित करना भी उसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।इसी दायित्व का निर्वहन तेज तर्रार व अनुभवी अयोध्या रेंज मे बाराबंकी जिले मे महिला थानाध्यक्ष के रुप मे तैनात कुमारी रत्ना दिखाई दे रही है। एसपी बाराबंकी व अन्य उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देश पर वे अपनी कुशल कार्यशैली,धैर्य और सूझबूझ के बल पर दर्जनों बिखरते परिवारों को फिर से जोड़ने का सराहनीय कार्य कर रही है।उनके कार्यशैली की तारीफ दूर दूर से अपनी फरियाद लेकर आने वाली महिलाओ तथा परिजनों ने किया।देखा जाये प्रतिदिन दूर से आने वाले न्याय की आसपास महिला थाना पहुंचने वाले पति–पत्नी के विवादों में उन्होंने केवल कानूनी प्रक्रिया तक स्वयं को सीमित नहीं रखा, बल्कि दोनों पक्षों को अपने सूझबूझ से समझाकर व उनकी समस्याओं को सुनकर और आपसी संवाद स्थापित कर अनेक परिवारों को टूटने से बचाने का काम कर रही है।मिशन शक्ति अभियान के तहत वे अयोध्या पुलिस द्वारा चलाए जा रहे महिला सुरक्षा व जन जागरुकता अभियानों को धरातल पर सफल बनाने में महिला थानाध्यक्ष बाराबंकी कुमारी रत्ना की भी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दे रही है।मिशन शक्ति अभियान के तहत वे अपनी टीम के साथ महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा हेल्पलाइन सेवाओं के प्रति जागरूक करने में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान कर रही है।वही जिले मे आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों, मेलों, धार्मिक आयोजनों एवं विशेष अभियानों में भी उनकी सक्रिय भूमिका निभा रही है।बताते चले कि बाराबंकी में आयोजित बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान महिला सुरक्षा, शिकायत

निस्तारण और जनसंपर्क के क्षेत्र में उनकी कार्यशैली को व्यापक सराहना मिली है।इस संबंध मे महिला थानाध्यक्ष बाराबंकी कुमारी रत्ना का मानना है कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास का संबंध जितना मजबूत होगा,समाज उतना ही सुरक्षित और सशक्त बनेगा।यही कारण है कि उनके पास पहुंचने वाली महिलाओं को केवल कानूनी सहायता ही नहीं, बल्कि भावनात्मक संबल और न्याय का भरोसा भी मिलता है।

14 अगस्त को निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा,तैयारियों को लेकर पत्रकारों की बैठक सम्पन्न

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त को प्रस्तावित भव्य तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर बुधवार को सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में पत्रकारों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।बैठक में तिरंगा यात्रा को सफल और भव्य बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।साथ ही सभी पत्रकारों से अधिक से अधिक संख्या में सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की गई।बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार बीएस लाठी ने कहा कि वर्ष 2025 में 14 अगस्त को निकाली गई पहली तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक और बेहद सफल रही थी।इस वर्ष 14 अगस्त 2026 को उससे भी अधिक भव्य एवं आकर्षक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति का संदेश देगी। तिरंगा यात्रा के संयोजक आकाश गुप्ता ने बताया कि यात्रा को चार प्रमुख जोन में विभाजित किया गया है। यात्रा सुबह 11 बजे सहादतगंज चौराहे से शुरू होगी और सिविल लाइन पत्रकार चौराहा, उदया चौराहा होते हुए नया घाट पहुंचेगी।यहां समापन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।आकाश सोनी ने कहा कि तिरंगा यात्रा महज एक आयोजन नहीं, बल्कि जन–जागरूकता का अभियान भी है।सभी पत्रकार राष्ट्रभक्ति का संदेश जन–जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसमें शामिल होंगे। समीर शाही ने सभी पत्रकारों से सुबह 10रू30 बजे तक सहादतगंज चौराहे पर पहुंचने और अनुशासित ढंग से यात्रा में सहभागिता करने की अपील की।अजय श्रीवास्तव श्अज्जूश ने कहा कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के पत्रकार तिरंगा यात्रा में शामिल होकर इसे ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करें।वहीं रूपेश श्रीवास्तव ने कहा कि यह यात्रा पत्रकारों की एकजुटता, राष्ट्रप्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बनेगी।अखंड सिंह ने कहा कि सभी पत्रकार हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति गीतों के साथ नया घाट तक यात्रा में शामिल होंगे और राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संदेश देंगे।वरिष्ठ पत्रकार आशु श्रीवास्तव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों को यात्रा में शामिल कराने का जो दायित्व उन्हें सौंपा गया है, उसका वह पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे।बैठक में मौजूद अन्य पत्रकारों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और तिरंगा यात्रा को सफल बनाने का संकल्प लिया। बैठक की जानकारी मीडिया प्रभारी राजेंद्र दुबे एवं अनिल निषाद ने दी।इस अवसर पर क्षितिज साधवानी, अपूर्व पाठक, सौरभ शुक्ला, राघवेंद्र शुक्ला, सुबोध श्रीवास्तव, करन प्रजापति, नरेंद्र मिश्रा, गुलजार खान, चंद्रधर द्विवेदी, अंकुर श्रीवास्तव, शिवेंद्र सिंह, सुमित यादव, नवनीत कौशल, बृजेश सिंह, अभिषेक उपाध्याय, देवेंद्र कुमार, धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे।

नाका पर शौचालय एवं मकबरा में पंप का महापौर ने किया लोकार्पण

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। नगर निगम अयोध्या द्वारा शहर की स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने गांधी आश्रम के सामने आबकारी कार्यालय के बगल नव–निर्मित सुलभ शौचालय का लोकार्पण किया। इस शौचालय का निर्माण लगभग सात लाख रुपये की लागत से कराया गया है। इसके साथ ही मकबरा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 22 हॉर्स पावर क्षमता के नए पंपसेट का भी लोकार्पण किया गया। इसकी लागत 7.44 लाख रुपये है।इस अवसर पर महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि रामनगरी में स्वच्छता और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि नगरवासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध

कराने के लिए नगर निगम निरंतर विकास कार्य करा रहा है। सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण से स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा, वहीं नए पंपसेट की स्थापना से संबंधित क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति और अधिक सुचारु एवं प्रभावी होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नगर निगम द्वारा संचालित सभी जनसुविधाओं का नियमित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।लोकार्पण कार्यक्रम में महाप्रबंधक जलकर सौरभ कुमार, पार्षद सूर्यकुमार तिवारी श्सूर्याश, निखिल श्रीवास्तव, विकास कुमार,भाजपा नेता आलोक द्विवेदी, मंडल अध्यक्ष हेमंत जायसवाल, महेश जायसवाल, आनंद जायसवाल, कृष्णानंद पांडेय, रामानंद पांडेय, सत्यम गुप्ता, रामकरन कोरी, जोनल अधिकारी विनय प्रकाश सिंह, सहायक अभियंता भरत कुमार वर्मा, अवर अभियंता अरुण सिंह तथा अनु जायसवाल सहित नगर निगम के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

पूरा कलंदर पुलिस क्षेत्र से दो की खुली हिस्ट्रीशीट

अयोध्या। एसएसपी डॉ0 गौरव ग्रोवर के निर्देशन में थाना पूराकलन्दर क्षेत्र से 02 अपराधियों को दुराचारी घोषित करते हुए उसके आपराधिक इतिहास के अनुरूप (ब) प्रकार की हिस्ट्रीशीट खोली गई है।जिन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है।उसमे राज सिंह पुत्र सूर्यभान सिंह निवासी कन्दैला थाना पूराकलन्दर जनपद अयोध्या व लल्लन सिंह पुत्र शंकर सिंह निवासी दौलतपुर थाना पूराकलन्दर जनपद अयोध्या शामिल है।

ट्रक की टक्कर से डीसीएम चालक की मौत, प्राथमिकी

भदोही, (संवाददाता)। कोतवाली क्षेत्र के कोठरा गांव के पास हाइवे पर रविवार की देर रात ट्रक की टक्कर से डीसीएम चालक राकेश की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज किया। अलुआ निवासी रमेश कुमार ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि मेरा भाई राकेश दो अगस्त की रात दो बजे अपनी डीसीएम लेकर प्रयागराज से वाराणसी की ओर जा रहा था। जैसे ही कोठरा के पास हाईवे पर पहुंचा एक ट्रक ने टक्कर मार दिया। जिससे उसके भाई की मौके पर ही मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक राजेश सिंह ने कहा कि अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

कास्टमेटिक की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जला

भदोही, (संवाददाता)। नगर के अहमदगंज गजिया में सोमवार को तड़के कॉस्मेटिक्स की दुकान में आग लग गई। आग से करीब चार लाख रुपये के सामान जलकर नष्ट हो गए। सही लोकेशन न मिलने से दमकल विभाग डेढ़ घंटे बाद मौके पर पहुंचे, तब तक स्थानीय लोग आग पर काबू पा चुके थे। नगर निवासी अजय सेठ ने किरण चौरसिया के किराए के मकान में कास्मेटिक्स की दुकान खोल रखी है। सोमवार को सुबह लगभग चार बजे लोगों ने दुकान से धुआं उठते देखा तो सकते में आ गए। कुछ ही देर में धुआं बढ़ गया तो लोगों ने खुद ही आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। मकान मालिक किरण चौरसिया ने बताया कि घटना की सूचना दमकल विभाग को दी गई थी, लेकिन दमकल के आने से पहले लोग आग को बुझाने में लग गए थे और किसी तरह आग को बुझा लिया था। बताया गया है कि दमकल विभाग को लोकेशन की सही जानकारी नहीं बताए जाने से वे करीब डेढ घंटे देरी से पहुंच सका था। किरण चौरसिया ने बताया कि आग किस कारण से लगी। इसकी जानकारी नहीं हो सकी, लेकिन शार्ट सर्किट से आग लगने की घटना हो सकती है। दमकल विभाग और कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही थी। मकान मालिक के अनुसार दुकान में करीब चार लाख रुपये के कास्मेटिक के सामान के साथ–साथ बैटरी, इनवर्टर, फर्नीचर आदि सामान नष्ट होने से बचाया नहीं जा सका।

आईटीएमएस प्रणाली ने खोली यातायात नियमों के तहत तीन माह में 36,869 वाहनों का चालान,जुलाई में नियम के उल्लंघन में आई कमी

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। नगर की यातायात व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा लागू की गई इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) अब प्रभावी परिणाम देने लगी है।अत्याधुनिक कैमरों और स्वचालित निगरानी प्रणाली के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।पिछले तीन माह में कुल 36,869 वाहनों के चालान किए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि बड़ी संख्या में लोग अब भी यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।आईटीएमएस के माध्यम से बिना हेलमेट वाहन चलाना, ट्रिपल राइडिंग, रेड लाइट जंप करना, गलत दिशा (रॉन्ग डायरेक्शन) में वाहन चलाना तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर स्वचालित रूप से चालान जारी किए जा रहे हैं।नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार मई माह में सर्वाधिक 17,278 चालान किए गए, जबकि जून में 15,502 वाहनों पर कार्रवाई हुई। लगातार निगरानी और जागरूकता अभियानों का सकारात्मक प्रभाव जुलाई में दिखाई दिया, जब नियम के उल्लंघन के मामलों में कमी दर्ज की गई और 4,089 वाहनों के चालान किए गए।नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के तीनों जोनों में आईटीएमएस प्रणाली लागू कर दी गई है। इसके अंतर्गत निषाद राज चौराहा, टेढ़ी बाजार चौराहा, उदया चौराहा, नियावां, रिकाबगंज, नाका, पुलिस लाइन, सिविल लाइन, देवकाली चौराहे सहित 20 प्रमुख चौराहों पर हाई–रिजॉल्यूशन कैमरे और स्मार्ट ट्रैफिक मॉनिटरिंग उपकरण स्थापित किए गए हैं। ये कैमरे चौबीसों घंटे यातायात गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं।उन्होंने बताया कि इस प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में नागरिकों को पुलिस सहायता एक बटन दबाते ही उपलब्ध कराई जाती है। इससे न केवल कानून–व्यवस्था को मजबूती मिली है, बल्कि सड़क सुरक्षा भी बेहतर हुई है।नगर आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वह हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाएं। ट्रैफिक सिग्नलों का पालन करें। गलत दिशा में वाहन न चलाएं। यातायात नियमों का ईमानदारी से अनुपालन करें। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और अनावश्यक चालान से भी बचा जा सकेगा।

वाटर पार्क के लिए बिछा कटा तार बना काल, मासूम रौनक की करंट से मौत– एक हिरासत में

गोरखपुर, (संवाददाता)। सुरौली थाना क्षेत्र के बढ़ेया गांव के सोनार टोला में रविवार की शाम एक व्यक्ति के दरवाजे पर खेल रहे डेढ़ वर्षीय रौनक की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घर के सामने खेलते हुए बच्चा सड़क के दूसरी तरफ वाटर पार्क के पास बिछाए गए बिजली के तार के संपर्क में आ गया। परिवार वाले तत्काल बिजली आपूर्ति बाधित करवाकर मासूम को मेडिकल कॉलेज ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। पुलिस ने वाटर पार्क की मालकिन जिला पंचायत सदस्य के पति को थाने में बैठा लिया है। बढ़ेया गांव निवासी जगदीश चौहान का बेटा रौनक चौहान रविवार की शाम घर के सामने खेलते–खेलते सड़क के

उस पार चला गया। वहां वाटर पार्क के लिए बिजली का तार बिछाया गया था। परिवार वालों के अनुसार, तार एक स्थान पर कटा हुआ था। जैसे ही मासूम ने उसे पकड़ा, वह करंट की चपेट में आ गया। बच्चे की चीख सुनते ही परिवार वाले और आसपास के लोग दौड़ पड़े। तत्काल बिजली आपूर्ति बाधित करवाकर मासूम को करंट से अलग कर मेडिकल कॉलेज ले गए मगर तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही सुरौली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया गया। मासूम की मौत से परिवार में चीख–पुकार मच गई। मां अंबालिका देवी बेटे को याद कर बार–बार बेहोश हो जा रही थीं, जबकि दादा रमापति चौहान का भी रो–रोकर बुरा हाल था। वह अपने माता पिता का इकलौता संतान था ।

पहली मंजिल से हटाया गया दवा वितरण केंद्र, भूतल से मिलेगी दवा

गोरखपुर, (संवाददाता)। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों के लिए राहत भरी पहल की गई है। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की लंबे समय से चली आ रही परेशानी को दूर करते हुए दवा वितरण केंद्र को पहली मंजिल से भूतल पर स्थानांतरित कर दिया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब मरीजों और उनके तीमारदारों को दवा लेने के लिए सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी। इससे विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार और चलने–फिरने में असमर्थ मरीजों को काफी सुविधा मिलेगी। अब तक नेहरू अस्पताल का दवा वितरण केंद्र पहली मंजिल पर संचालित होता था। डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद मरीजों को दवा प्राप्त करने के लिए ऊपर जाना पड़ता था। पहली मंजिल पर सर्जरी और ईएनटी

विभाग की ओपीडी भी संचालित होने के कारण वहां पूरे दिन मरीजों की भीड़ रहती थी। ऐसे में दवा लेने पहुंचे लोगों को लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता था। भीड़ के कारण आवागमन प्रभावित होता था और गंभीर मरीजों के साथ–साथ वरिष्ठ नागरिकों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अस्पताल प्रशासन को लगातार मिल रही शिकायतों और बढ़ते मरीजों के दबाव को देखते हुए दवा वितरण केंद्र को भूतल पर वातानुकूलित पर्चा काउंटर के पास स्थापित किया गया है। इससे मरीजों को पर्ची बनवाने और दवा लेने के लिए अलग–अलग मंजिलों पर नहीं जाना पड़ेगा। नई व्यवस्था से मरीजों का समय बचेगा, अनावश्यक भागदौड़ कम होगी और पहली मंजिल पर भीड़ का दबाव भी घटेगा। इससे सर्जरी और ईएनटी ओपीडी का संचालन भी पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित ढंग से हो सकेगा।

युवती के परिजनों की शिकायत पर टॉवर पर चढ़े युवक पर प्राथमिकी

भदोही, (संवाददाता)। कोतवाली के एक गांव में रविवार को प्रेमिका से शादी की जिद पर मोबाइल टॉवर पर चढ़े युवक पर सोमवार को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। युवती का आरोप है कि युवक विजय गौतम कुछ समय से बाजार आते–जाते परेशान कर रहा था।

बर्खास्त सिपाही की 10 घंटे पुलिस रिमांड

गोरखपुर, (संवाददाता)। कोतवाली क्षेत्र में 10 वर्षीय बालिका के अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी बर्खास्त सिपाही अभिषेक यादव की 10 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड अदालत ने मंजूर कर ली है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विजय बहादुर यादव की अदालत ने पुलिस को मंगलवार सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक पूछताछ की अनुमति दी है। कोतवाली पुलिस ने अदालत में दाखिल अर्जी में वारदात में प्रयुक्त धारदार हथियार की बरामदगी, घटनास्थल का पुनर्निर्माण और मामले से जुड़े अहम तथ्यों की पुष्टि के लिए कस्टडी रिमांड की मांग की थी।

तकनीकी खराबी से स्पाइसजेट की दिल्ली–मुंबई उड़ानें निरस्त

गोरखपुर, (संवाददाता)। गोरखपुर एयरपोर्ट से सोमवार को संचालित होने वाली स्पाइसजेट की दिल्ली और मुंबई की उड़ानें तकनीकी कारणों से प्रभावित रहीं। दिल्ली की फ्लाइट निरस्त होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे यात्रियों में नाराजगी देखने को मिली। अब यह विमान मंगलवार की सुबह आठ बजे आएगा और यहां से यात्रियों को लेकर उड़ान भरेगा। स्पाइसजेट की दिल्ली से आने वाली फ्लाइट का लैंडिंग समय शाम 6:30 बजे निर्धारित था। यह विमान गोरखपुर से शाम 6:50 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरता लेकिन निर्धारित समय पर विमान नहीं पहुंच सका। पहले फ्लाइट के एक घंटे लेट होने की जानकारी दी गई, बाद में इसे मंगलवार के लिए निरस्त कर दिया गया। वहीं, मुंबई से आने–जाने वाली शाम की फ्लाइट भी रद्द रही। मुंबई की फ्लाइट का गोरखपुर पहुंचने का समय शाम 5:15 बजे था, जबकि यहां से यात्रियों को लेकर विमान को शाम छह बजे रवाना होना था। एयरलाइंस की ओर से यात्रियों को पहले ही उड़ान निरस्त होने की सूचना दे दी गई थी। स्पाइसजेट के स्टेशन मैनेजर यशवंत सिंह ने बताया कि तकनीकी कारणों से विमान गोरखपुर नहीं आ सके, जिसके चलते उड़ान को निरस्त करना पड़ा।

गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा में तैनात स्नाइफर डॉग वेनमोर की कैंसर से मौत

गोरखपुर, (संवाददाता)। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले गोरखपुर पुलिस के स्नाइफर डॉग श्वेनमोरश का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वेनमोर जर्मन शेफर्ड नस्ल का नौ वर्षीय श्वान पिछले चार माह से कैंसर से जूझ रहा था। पुलिस लाइन में इलाज के दौरान उसने अंतिम सांस ली। स्नाइफर की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। एसएसपी डॉ. कौस्तुभ और एसपी सिटी निमिष पाटिल की मौजूदगी में उसे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वेनमोर को वर्ष 2018 में महज एक वर्ष की उम्र में बीएसएफ टेकनपुर (मध्य प्रदेश) से गोरखपुर लाया गया था। यहां डॉग स्क्वॉड ने उसे विस्फोटकों का पता लगाने की विशेष स्नाइफर ट्रेनिंग दी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उसे सुरक्षा ड्यूटी में लगाया गया

और उसने अपनी सूंघने की अद्भुत क्षमता से कई अहम सुरक्षा अभियानों में योगदान दिया। वेनमोर की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था थी। वह प्रतिदिन गोरखनाथ मंदिर परिसर की सघन जांच करता था। कैंसर की पुष्टि होने के बाद पिछले चार महीने से वह ड्यूटी से दूर था। पुलिस लाइन में उसका लगातार इलाज चल रहा था लेकिन मंगलवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। उसके निधन पर पुलिस लाइन में शोक सभा आयोजित की गई, ।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।